

Corporation should be wound up, as it has not been a commercially viable organisation. The Committee reiterated this recommendation in its "Action Taken" report on the said sixty-second Report. The committee's recommendation is under Government's consideration.

### बीजों के मूल्यों में उतार-चढ़ाव

2414. श्री गंगा चरण दीक्षित : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1972-73 वर्ष में बीजों के मूल्यों में क्या उतार-चढ़ाव रहा ; और

(ख) मूल्य बृद्धि के क्या कारण हैं ?

कृषि विभाग में राज्य मंत्री (श्री शी. पी. शौर्य) : (क) और (ख) राज्यीय बीज निगम और भारतीय राज्य कार्म निगम जैसे संस्थानों द्वारा बेचे गये मूल्य किसम के बीजों के मूल्यों में 1972-73 के दौरान आमतौर से कोई भारी उतार-चढ़ी नहीं हुई है। राज्यीय बीज निगम ने गेहूं के बीज का मूल्य 1971-72 में 170 रुपये से बढ़ा कर 1972-73 में 200 रुपया प्रति किंवद्वि कर दिया। बीज उत्पादकों को ऊंचे वसूली मूल्य दिए जाने के कारण यह बृद्धि आवश्यक हो गई थी। जहां तक भारतीय राज्य कार्म निगम का भागला है, इस निगम ने मूँग के बीजों का मूल्य 1972-73 में बढ़ाया था।

सुपर बाजार, नई दिल्ली में पूँजी निवेश और निवेशक की नियुक्ति की कठोरी

2415. श्री लंका चरण दीक्षित : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने सुपर बाजार, नई दिल्ली में अब तक कितनी पूँजी लगाई है; और

(ख) सुपर बाजार, नई दिल्ली के निवेशक की नियुक्ति सम्बन्धी मापदंड क्या है

और अंतर्राष्ट्रियों द्वारा निवेशक के लकाव की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि विभाग में राज्य मंत्री (श्री अच्छासाहिब शी. लिखे) : (क) भारत सरकार ने कोआपरेटिव स्टोर लिमिटेड (सुपर बाजार), नई दिल्ली में अब तक अंतर्राष्ट्रिय अंतराल के रूप में 66.76 लाख रुपये की धन राशि लगाई है। इसके अतिरिक्त, 77.43 लाख रुपये की राशि बृहण और 7.22 लाख की अनुदान के रूप में दी गई थी (अृज में से सुपर बाजार ने वापसी-अदायगी की समय-अनुसूची के अनुसार 19.03 लाख ह० की राशि लोटा दी है)।

(ख) कोआपरेटिव स्टोर लिमिटेड, नई दिल्ली का उप-विधियों के अनुसार प्रत्यन्त समिति के नो सदस्य भारत सरकार द्वारा नामित किये जाते हैं और ये ल० सरकार के अलावा दूसरे अंतर्राष्ट्रियों द्वारा निर्वाचित किये जाने होते हैं। नामित निवेशकों का बयन सरकार द्वारा इस प्रकार किया जाता है कि वे समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले हों जिनमें अन्य गैर-सरकारी अधिकारों के माध्य-साध एक संबंध सदस्य और राज्यीय महाकारी उपभोक्ता परिसंघ, नई दिल्ली नगरपालिका, दिल्ली प्रशासन और केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि होते हैं।

### Short Supply of Small Tractor in Madhya Pradesh

2417. SHRI G. C. DIXIT: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether small tractors are in short supply in Madhya Pradesh as compared to the other States; and

(b) if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE